



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 1986/फाल्गुन 26, 1907

No. 133]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 17, 1986/PHALGUNA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1986

अधिसूचनाएं

सा.का.नि. 505(अ) केन्द्रीय सरकार, हथकरधा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च, 1986 को उस तारीख के रूप में नियत करता है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[स. 117(3-आर)डी सी.एच./85ई एण्ड एम.]

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 10th March, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 505(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Hand-looms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of the 1985), the Central Government hereby appoints the 31st day of March, 1986 as the date on which the said Act shall come into force

[No. DCH/17(3-R)/85-E&S]

सा.का.नि. 506(अ) केन्द्रीय सरकार, हथकरधा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) की धारा 19 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्,—

I सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इन नियमों का सक्षिप्त नाम हथकरधा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) नियम, 1986 है।

(II) ये 31 मार्च, 1986 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) अधिनियम में हथकरधा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 का 22) है;

(ख) प्राधिकृत अधिकारी स केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो केन्द्रिय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्राधिकृत किया जाता है,

(ग) तमूना में अधिनियम के उपबंधों के अधीन या इन नियमों के अधीन लिया गया किसी कपड़े का तमूना अभिप्रेत है,

3. सलाहकार समिति की स्थापना और गठन —(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित की जाने वाली समिति में एक अध्यक्ष और तीन से अनाधिक उतने अन्य सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) मलाहकार समिति की कार्यावधि सामान्यतया तीन वर्षों होगी परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि में पूर्वतः मलाहकार समिति का पुनर्गठन कर सकता है।

(3) मलाहकार समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के पद में त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई आकस्मिक रिक्ति नया नामनिर्देशन करके भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्ति उस अवधि के शेष भाग मात्र तक पद धारण करेंगे जिस तक अध्यक्ष या वह सदस्य जिसके स्थान पर नियुक्ति की जाती है, नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(4) मलाहकार समिति का अध्यक्ष अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा

परन्तु जहाँ अध्यक्ष मलाहकार समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ हो वहाँ वह मलाहकार समिति के किसी सदस्यो में से एक को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा।

(5) मलाहकार समिति के अधिवेशन ऐसे स्थानों और समयों पर होंगे जो अध्यक्ष द्वारा अध्वारित किए जाएं

परन्तु मलाहकार समिति का अधिवेशन वष में कम से कम एक बार आरक्षित वस्तुओं की सूची का पुनरीक्षण करने के लिए किया जाएगा।

4. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई जान वाली प्रक्रिया —

(1) जहाँ प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (2) के अधीन किसी वस्तु या वर्ग की वस्तु का अभिग्रहण करना है वहाँ वह अभिग्रहीत कपड़े का नमूना लेगा और उसे आग-आधा मीटर में अत्यन्त के तीन भागों में बाटेगा जिन्हें सावधानी पूर्वक पृथक-पृथक कन्टेनरों में सीलबन्द किया जाएगा और प्रत्येक कन्टेनर पर उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान, जिन्हें नमूना लिया गया है, लगाए जाएंगे तथा प्राधिकृत अधिकारी का चिह्न या मुद्रा भी लगाई जाएगी।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, इस प्रकार लिए गए नमूने के एक भाग को सम्बन्धित व्यक्ति को सौंपेगा और उम्क। उचित रसीद के रूप में उसके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति अपना हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने से इन्कार करता है तो प्राधिकृत अधिकारी एक अभिग्रहण जापन तैयार कर सकेगा और उस पर यह लेखबद्ध कर सकेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति अपना हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने से इन्कार करता है,

परन्तु यह और कि अभिग्रहण जापन सम्बन्धित व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक में उसके ज्ञान पत्र पर भेजा जाएगा और रजिस्ट्रीकृत डाक से दिए गए ऐसे प्रेषण को, उक्त प्रेषण में सात दिन की अवधि के भीतर, अभिग्रहण जापन से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने का सबूत माना जाएगा।

3(क) प्राधिकृत अधिकारी नमूने के दूसरे भाग का केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित परीक्षण प्रयोगशाला का या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त संस्थानों का जो किसी विशिष्ट क्षेत्र या प्रदेश के लिए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सामूहिक रूप से अधिसूचित किए जाने हैं, भेजेगा

परन्तु जहाँ ऐसी प्रयोगशाला या संस्थान इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया गया है वहाँ नमूना केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या प्रदेश के लिए उस निमित्त प्राधिकृत लोक विश्लेषण को परीक्षण के लिए भेजा जा सकेगा।

(ख) उपर्युक्त परीक्षण प्रयोगशाला या संस्थान या लोक विश्लेषण गसायनिक विश्लेषण द्वारा या किसी अन्य पद्धति से, जो वह ठीक समझे, यह अवधारित करने के लिए कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजा गया नमूना हथकरघों या पावरलूमों पर तैयार किया गया है या नहीं, आवश्यक परीक्षण करेगा और अपना निष्कर्ष प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के उपबन्धों अधीन रहते हुए, प्राधिकृत अधिकारी नमूने के तीसरे भाग का अपने पास उतना अवधि तक जितनी वह ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(5) प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन में वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पावरलूमों को उनके स्वामी या प्रचालक की उपस्थिति में अधिग्रहीत करेगा और पावरलूमों के अभिग्रहण का तथ्य और स्वामी या प्रचालक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान के रूप में ली गई रसीद को उत्पादक का लिखित में सम्मति करेगा तथा उसको एक प्रतिनिधि उस परिमर के, जहाँ पावरलूम प्रतिष्ठापित है, किसी सदस्य स्थान पर लगाई जाएगी

परन्तु जहाँ उक्त पावरलूम का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है वहाँ प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के परन्तु में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपना सकता है।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अभिग्रहीत माल का ऐसी अवधि तक, जैसी वह ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(7) प्राधिकृत अधिकारी तलाशी और अभिग्रहण के पश्चात् मामला उस स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का जिसे मामले का अन्वेषण करने की अधिकारिता है रिपोर्ट करेगा।

(8) जब भी प्राधिकृत अधिकारी का किसी व्यक्ति से विरोध किए जाने या झूठ की आशंका हो वहाँ तलाशी और अभिग्रहण के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए स्थानीय पुलिस थाने की सहायता प्राप्त कर सकेगा।

(9) इस नियम के उपबन्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के, तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित, उपबन्धों के अनुरिक्त है और उनका न्यूनीकरण नहीं करने है।

5. अभिग्रहीत वस्तुओं का निष्पादन — अधिनियम की धारा 10 के अधीन केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समग्रहृत वस्तुएं या वर्ग की वस्तुएं केवल निम्नलिखित विक्रय माध्यमों की मार्फत बेची जाएगी अर्थात् —

(क) महकारी प्रभिकरण

(ख) राष्ट्रीय महकारी उपभोक्ता सच में सम्बद्ध उचित मूल्य दुकानें;

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या हस्तशिल्प और हथकरघा निगमा या अपेक्षम एम्पोरिया द्वारा खोली गई उचित मूल्य दुकानें

परन्तु केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समग्रहृत पावरलूम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए पावरलूम मेवा केन्द्रों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अध्वारित की गई अवज्ञित लागत पर अतर्गित किए जा सकते हैं या सौंपे जा सकते हैं।

[स 117 (3-आर) टीएमएच/85-ई एडएम]

चरनदाम चौमा,
मयकत मचिव

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985, (22 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Rules, 1986.
- (2) They shall come into force on and from the 31st day of March, 1986.
2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) “Act” means the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (22 of 1985) ;
 - (b) “authorised Officer” means any officer subordinate to the Central Government or to the State Government or to any Authority, as may be authorised by the Central Government under Section 7 of the Act ;
 - (c) “sample” means a sample of any cloth taken under the provisions of the Act or under these rules.

3. Establishment and constitution of Advisory Committee.—(1) The Advisory Committee to be constituted under sub-section (1) of section 4 of the Act shall consist of a Chairman and such other members, not exceeding thirty, as may be nominated by the Central Government.

(2) The Advisory Committee shall normally have a tenure of three years :

Provided that if the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may reconstitute the Advisory Committee earlier than the aforesaid period of three years.

(3) A casual vacancy occurring in the offices of the Chairman or members of the Advisory Committee by resignation or otherwise shall be filled by a fresh nomination and the persons nominated to fill the vacancy shall hold office only for the remainder of the term for which the Chairman or, as the case may be, the members whose place he takes, was nominated.

(4) The Chairman of the Advisory Committee shall preside at its meetings :

Provided that where the Chairman is unable to attend any meeting of the Advisory Committee, he shall nominate one of the members of the Advisory Committee to preside over the meeting

(5) The Advisory Committee may meet at such places and at such times as may be determined by the Chairman:

Provided that the Advisory Committee shall meet at least once a year to review the list of reserved articles.

4. Procedure to be followed by Authorised Officer.—(1) Where an authorised officer seizes any article or class of articles under sub-section (2) of section 8 of the Act, he shall take a sample of the seized cloth and divide it into three parts measuring not less than half metre each which shall be sealed carefully in separate containers and the signature or thumb impression of the persons from whom the samples has been taken, shall be fixed on each container along with the mark and seal of the authorised officer.

(2) The authorised officer shall hand over one part of the sample so taken to the person concerned and secure from him proper acknowledgement for the same by way or signature or thumb impression :

Provided that where such persons refuses to sign or put his thumb impression, the authorised officer may prepare a seizure memorandum and record therein that the person concerned has refused to sign or put his thumb impression:

Provided further that the seizure memorandum shall be sent to the person concerned through registered post at his known address and such despatch through registered post shall be taken as a proof of the person concerned having received the seizure memorandum within a period of seven days of the said despatch.

(3) (a) The authorised officer shall send the second part of the sample to a testing laboratory set up by the Central Government or the State Government or to institutions recognised by the Central Government or State Government as may be duly notified, from time to time, by the Central Government or, as the case may be, by the State Government for a particular area or zone in this behalf:

Provided that where such laboratory or institution has not been so notified, the sample may be sent for being tested to a public analyst authorised in this behalf for a particular area or zone by the Central Government or, as the case may be, by the State Government.

(b) The testing laboratory or institution or public analyst aforesaid shall perform the necessary tests either by chemical analysis or by any other method, as deemed fit, to determine whether the sample sent by the authorised officer was made on handlooms or powerlooms and report the findings to the authorised officer.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 8 of the Act, the authorised officer shall retain the third part of the sample and keep it in safe custody for such period as he may deem necessary.

(5) The authorised officer shall seize the powerloom used for production of articles in violation of orders issued under section 3 of the Act in the presence of the owner or, as the case may be, the operator of the powerloom and the fact of seizing the powerloom along with the acknowledgement of the

owner or of the operator by way of his signature or thumb impression shall be intimated to the producer in writing and a copy thereof shall be affixed at some conspicuous place in the premises where the powerloom is installed:

Provided that where it is not practicable to seize the said powerloom, the authorised officer may follow the procedure specified in the proviso to sub-section (2) of Section 8 of the Act.

(6) Subject to the provisions of sub-section (3) of section 8, the authorised officer shall keep the seized goods in safe custody for such period as he may deem necessary.

(7) The authorised officer, after search and seizure, shall also report the matter to the officer in charge of the local police station having jurisdiction to investigate the case.

(8) Whenever the authorised officer apprehends any resistance or trouble from any person, he may take assistance from the local police station for carrying out his duties to search and seizure.

(9) The provisions of this rule shall be in addition to and not in derogation of the provisions of

the Code of Criminal Procedure 1973, (2 of 1974), relating to searches and seizures.

5. Disposal of forfeited articles.—The articles of class of articles forfeited to the Central Government under section 10 of the Act shall be sold only through the following channels of sales, namely :—

- (a) Cooperative outlets;
- (b) fair price shops affiliated to National Co-operative Consumers' Federation;
- (c) fair price shops opened by the Central Government or State Government or Handicrafts and Handloom Corporations or Apex Emporia :

Provided that the powerlooms forfeited to the Central Government may be transferred or handed over to powerloom service centres set up by the Central Government or the State Government on depreciated cost to be determined by the Central Government from time to time.

[No. DCH/17(3-R)/85-E&S]
C. D. CHEEMA, Jt. Secy.